(31)

वि0 सलाहकार
से अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0–गवर्नेंस विभाग

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक– ITSec2/JSAC-1/2021/IT - 31 राँची, दिनांक– 06.01.2022

प्रेषक,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, हिनू, राँची।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय– राज्य में उपग्रह डेटा, ड्रोन–सर्वेक्षण डेटा या एरियल फोटोग्राफ के भू–संदर्भ (Georeferencing) हेतु Ground Control Points (GCP) के अधिष्ठापन एवं दुमका जिले के दुमका प्रखण्ड में High Resolution Satellite Data with DEM/DSM के अध्ययन आधारित पायलट परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राशि 3,00,00,000/– (तीन करोड़ रु0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग राज्य की प्रगति हेतु नवीन तकनीकों को आत्मसात करने हेतु सतत प्रगतिशील है। इन नवीन तकनीकों से राज्य की संवहनीय प्रगति एवं नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराता है।

Ground Control Points (GCP) पृथ्वी की सतह पर एक सुपरिभाषित त्रिआयामी {अक्षांश (X), देशांतर (Y) एवं समुद्र तल से ऊंचाई (Z)} स्थान हैं। ये स्थान किसी भी उपग्रह डेटा, ड्रोन–सर्वेक्षण डेटा या एरियल फोटोग्राफ के भू–संदर्भ (Georeferencing) में बहुत उपयोगी हैं। सभी प्रकार की भूमि रिकॉर्ड परियोजना के Image Interpretation में Cadastral Level Accuracy के साथ–साथ अन्य भूमि रिकॉर्ड परियोजनाओं की सटीकता हेतु व्यापक रूप से वितरित GCP का होना आवश्यक है। GPS सर्वेक्षण की शुद्धता को बढ़ाने हेतु राज्यभर में GCP का एक नेटवर्क होना आवश्यक है।

High Resolution Satellite Data with DEM/DSM के अध्ययन आधारित परियोजना दुमका जिले के दुमका प्रखण्ड में पायलट रूप में क्रियान्वित की जानी है। इस परियोजना में उक्त प्रखण्ड का विस्तृत डेटाबेस High Resolution Satellite Data के चार (4) layers यथा– Infrastructure layer, Natural resources layer, Digital Elevation Model (DEM)/Digital Surface Model (DSM), Generation of slope and gradient layer के मदद से तैयार किया जाना है। इसके मदद से उक्त क्षेत्र के Land Cover classifications एवं pattern analysis को सटिकतापूर्वक दर्शाते हुए अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह पर होने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्तम परिवर्त्तन को पता लगाने के साथ–साथ इसे निर्धारित भी किया जा सकता है। उक्त दोनों परियोजनायें झारखण्ड राज्य के जी0आई0एस0 पोर्टल का हिस्सा होंगे।

2. झारखण्ड राज्य में, Survey of India (SOI) ने राज्य भर में 64 GCP की स्थापना की है, परन्तु राज्य के विस्तृत सर्वेक्षण एवं Georeferencing of Very High-Resolution Satellite (VHRS) data हेतु इनकी उपलब्धता प्रर्याप्त नहीं है। इस निमित्त राज्य में कम से कम प्रत्येक 20 से 25 किलोमीटर पर अतिरिक्त 500 GCP की आवश्यकता है। ये GCP SOI द्वारा अधिष्ठापित GCP से दूरी के अनुसार प्राथमिक (Primary) एवं द्वितीयक (Secondary) GCP होंगे।

3. Ground Control Points (GCP) के अधिष्ठापन हेतु विनिर्देशः–

(क) आर0सी0सी0 पिलर 30 x 30 x 100 सेंटीमीटर

(30)

(ख) नियंत्रण बिंदु जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर और जमीन के अंदर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए।

(ग) स्तंभ के चारों और 150 x 150 x 5 सेंटीमीटर का एक पी0सी0सी0 स्लैब जिसके ऊपर रंगीन पेंट है।

(घ) चयनित स्थल आकाश के लिए खुला और स्पष्ट होना चाहिए और भवन, टावर या पेड़ जैसी किसी भी ऊंची संरचना के नजदीक नहीं होना चाहिए।

4. परियोजना का क्रियान्वयन जैसेक द्वारा किया जाना है।

बजट की अनुमानित विवरणीः–

S. No.	Item/Activities	Unit Price	Cost (in Lakh)
1	Establishment of GCP and monumentation for 500 GCPs covering entire Jharkhand State	46,000 per GCP	230.00
2	Pilot Study for utilization of High Resolution satellite data along with DEM/DSM for Dumka Block of Dumka District.		30.37
3	Data Processing Cost (including manpower)		20.00
	Sub Total		280.37
	Institutional and Overhead charges @ 7%		19.63
	Grand Total		**300.00**
			(Rs. Three Crore Only)

उक्त टेबल में वर्णित बजट की विवरणी अनुमानित है एवं इसके क्रियान्वयन में अपनाई गई विधा अर्थात् निविदा इत्यादि के पश्चात् इसमें अंशतः परिवर्त्तन हो सकता है।

उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने राज्य में उपग्रह डेटा, ड्रोन–सर्वेक्षण डेटा या एरियल फोटोग्राफ के भू–संदर्भ (Georeferencing) हेतु Ground Control Points (GCP) के अधिष्ठापन एवं दुमका जिले के दुमका प्रखण्ड में High Resolution Satellite Data with DEM/DSM के अध्ययन आधारित पायलट परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राशि 3,00,00,000/– (तीन करोड़ रु0) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

5. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2203 तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–99–जी0आई0एस0 रिमोट सेंन्सिंग, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 81– सूचना संचार एवं संचरण सेवाएँ, विपत्र कोड– 45S22030079699000781 के अंतर्गत किया जाएगा।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, राँची होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से कर झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर के P/L Account में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

7 राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दि0 17.04.98 में दिए गए दिशा–निर्देश के तथा अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

8. स्वीकृत राशि के व्यय के अंकेक्षण का अधिकारी राज्य सरकार एवं महालेखाकार, झारखण्ड का होगा।

9. राशि का अपवर्त्तन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय तथा राशि का व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप एवं प्रक्रियात्मक हो अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे।

10. निदेशक, जैसेक स्वीकृत राशि का व्यय ब्यौरा/उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के सचिव
5.1.21

Skr16.09.21

29

ज्ञापांक :- 31 रांची, दिनांक 06.01.2022

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 31 रांची, दिनांक : 06.01.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा/विपत्र शाखा, (दो प्रतियों में)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, झारखंड स्पेश एपलिकेशन सेंटर, राँची/श्री देशबंधु मिश्रा, परामर्शी, SeMT, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Skr16.09.21

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1669

पत्रांक संख्या :- 31

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक दिनांक :- 06/01/2022

प्रेषक,

KRIPA NAND JHA
SECRETARY
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY & EGOVERNANCEPR

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : GCP

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के, राज्य स्कीम के
मुख्यशीर्ष - 2203-तकनीकी शिक्षा
उपमुख्य शीर्ष - 00-तकनीकी शिक्षा
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	₹ 3,00,00,000.00
कुलराशि :-	**₹ 3,00,00,000.00**

Run Date: 06/01/2022

10 93 96 167

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
45S220300796990781	99 - जी०आई०एस० रिमोट सेन्सिंग	81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी SUNIL KUMAR PODDAR (PRJSCT001), UNDER SECRETARY होंगे तथा राशि ₹ 3,00,00,000.00/- की निकासी Project Bld कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

6.1.22

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से